

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1001-दो/18

जिला-सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-04-17	<p>आवेदकगण के अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरौदिया द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-27/2005-66 में पारित अतिरिम आदेश दिनांक 2.2.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष निरनानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय व जयपत्र दिनांक 21.12.2016 पर दृष्टिपात किये बगैर मनमाने ढंग से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र0डी0-2 के आधार पर फर्द बटान बुलाये जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त किया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि दिनांक 13.2.17 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का विधि विरुद्ध निराकरण किया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में</p>	

-2-प्रकरण कमांक निगरानी 1001-दो/18

संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता इनकसिंह द्वारा प्रस्तावित फर्द बटान पर यह आपत्ति उठाई गई कि प्रस्तावित फर्द बटान में संशोधित प्रविष्टि के कॉलम में खसरा न० 46 रकवा 3.30 एकड में से कय की गई भूमि 0.267 है० के स्थान पर रकवा 0.162 है० भूमि दी जानी प्रस्तावित की है जो कि विधि विरुद्ध होकर दोषयुक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है साथ ही खसरा न० 51/1 रकवा 3.075 है० में से अनावेदक द्वारा 0.615 है० भूमि कय किया जाना बताया जबकि प्रस्तावित फर्द बटान में अनावेदक लक्ष्मण बजाज को 0.061 है० भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया है जो कि कय की गई भूमि से काफी कम है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र में उल्लेखित कय शुदा भूमि विपरीत माना है। अतः नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर का आदेश दिनांक 2.2.17 निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुये एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये प्रकरण में सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करें।


सदस्य